वस्त्र निर्यात छूट योजना में असंतुलन से प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

श्रम प्रधान उद्योग कर रहा है घाटे का सामना

■ विशेष गरिमा

जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान

को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए 'मेक इन इंडिया' की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फ़ेर रहे हैं। विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने कहा, ह्लकपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, ह्वक्कइ ने कहा ह्लटधट्टएड्ढख योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है।

इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। स्क्रिप पर इतने ज्यादा डिस्काउंट से आयातकों को तो फायदा हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, 16 अरब डॉलर के कुल परिधान निर्यात में करीब 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होती है, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए बनती है। व्यापक स्तर पर, इस पर 20 से 25 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाता है, इससे परिधान क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मार्जिन पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए का सीधा असर पड़ता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के कपड़ा क्षेत्र को अन्य कम लागत वाले देशों जैसे बांग्लादेश और वियतनाम (कम श्रम और विनिर्माण लागत के कारण) के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना था। मांग सरकार की मंशा के अनुरूप रही है, जो हमेशा निर्यातकों को प्रतिपूर्ति करने की थी, लेकिन स्क्रिप के डिस्काउंट के कारण, इस पूरी योजना का उद्देश्य और लक्ष्य विफल हो गया है। अपने मौजूदा स्वरूप में, स्क्रिप पर डिस्काउंट से आयातकों को लाभ हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित फायदा उठा रहे हैं।

राजस्थान कपड़ों का सबसे बड़ा विनिर्माता

गोविन्द गोपाल सिंह

जयपुर (नवयत्न)। राजस्थान कपड़ों का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है, जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और वर्ष 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देशभर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। हालांकि सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से वस्त्र उद्योग प्रभावित

जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीनें प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (RoSCTL) के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है।

ऋस्ह्रक्र को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं।

विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट

एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (GEAR) ने कहा, कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है।

विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, लश्क्रू ने कहा RoSCTL योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। स्क्रिप पर इतने ज्यादा डिस्काउंट से आयातकों को तो फायदा हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, 16 अरब डॉलर के कुल परिधान निर्यात में करीब 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होती है, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए बनती है। व्यापक स्तर पर, इस पर 20 से 25 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाता है, इससे परिधान क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मार्जिन पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए का सीधा असर पड़ता है।

इस योजना का उद्देश्य भारत के कपड़ा क्षेत्र को अन्य कम लागत वाले देशों जैसे बांग्लादेश और वियतनाम (कम श्रम और विनिर्माण लागत के कारण) के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना था। मांग सरकार की मंशा के अनुरूप रही है, जो हमेशा निर्यातकों को प्रतिपूर्ति करने की थी, लेकिन स्क्रिप के डिस्काउंट के कारण, इस पूरी योजना का उद्देश्य और लक्ष्य विफल हो गया है। अपने मौजूदा स्वरूप में, स्किप पर डिस्काउंट से आयातकों को लाभ हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित फायदा उठा रहे हैं। यह दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने के बजाय इस पूरी योजना के उद्देश्य और लक्ष्यों पर ही पानी फेर दे रहा है।

अगर सरकार तत्काल RoSCTL की संरचना में संशोधन नहीं करती है, तो चिंता है कि लागत अक्षमताओं के कारण उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो सकता है। सरकार से उचित मदद न मिलने के कारण एक बार फिर परिधान मांग को अन्य कम लागत वाले देशों में स्थानांतरित कर देगी।

राजस्थान कपड़ों का सबसे बड़ा विनिर्माता

❒ दिव्य संचेतना

जयपुर। राजस्थान कपड़ों का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है, जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और वर्ष 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान के परिधान निर्यातकों

को भी देशभर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। हालांकि सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं। गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष विमल शाह ने कहा कि कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इससे निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, जीईएमए के सदस्य विमल जिंदल ने कहा कि योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

■ दिव्य राष्ट्र

जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीनें प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (रोशक्टली) के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के

समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। रोशक्टली को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए 'मेक इन इंडिया' की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फ़ेर रहे हैं।विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (गियर) ने कहा, "कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं।

इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, गैमा ने कहा "रोशक्टली योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। स्क्रिप पर इतने ज्यादा डिस्काउंट से आयातकों को तो फायदा हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, 16 अरब डॉलर के कुल परिधान निर्यात में करीब 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होती है, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए बनती है। व्यापक स्तर पर, इस पर 20 से 25 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाता है, इससे परिधान क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मार्जिन पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए का सीधा असर पड़ता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के कपड़ा क्षेत्र को अन्य कम लागत वाले देशों जैसे बांग्लादेश और वियतनाम (कम श्रम और विनिर्माण लागत के कारण) के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना था। मांग सरकार की मंशा के अनुरूप रही है, जो हमेशा निर्यातकों को प्रतिपूर्ति करने की थी, लेकिन स्क्रिप के डिस्काउंट के कारण, इस पूरी योजना का उद्देश्य और लक्ष्य विफल हो गया है।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। RoSCTL को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं। श्री विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने कहा, कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। श्री विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, GEMA ने कहा RoSCTL योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है।

सरकार नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे: जीईएआर

■ जलतेदीप, जयपुर, कासं,

■ गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने मार्जिन में हो रहे नुकसान को लेकर जताई चिंता

राजस्थान के परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जीईएआर) ने कहा, 'कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, ने कहा आरओएससीटीएल योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट

के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। स्क्रिप पर इतने ज्यादा डिस्काउंट से आयातकों को तो फायदा हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। बता दें राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

■ जगत क्रान्ति

जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए 'मेक इन इंडिया' की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फ़ेर रहे हैं। श्री विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (ह्वब्इट) ने कहा, ह्नकपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है।ङ्क श्री विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, ब्क्खइ ने कहा ह्नटधड्डएड्ख योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं।

वस्त्र निर्यात छूट योजना में असंतुलन से परिधान-वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा प्रभावित

2029 तक 209 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करेगा रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय

महानगर संवाददाता

जयपुर। 'राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है। राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग 2500 करोड़ रुपए का है। देश भर में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक वर्तमान में 2 लाख मशीनें प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं। इनका मूल्य 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है, जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दे रहा है। 2029 तक यह उद्योग 209 अरब डॉलर के आकंड़े को पार करेगा।' यह विचार सोमवार को गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष विमल शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेन-देन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेन-देन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप्स को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सताने की भी बात कही।

वहीं एक्सपोर्ट प्रमोशन एईपीसी सदस्य विजय जिंदल ने कहा कि यह योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है।

वर्ल्ड एंट्रेप्रेन्योर्स डे : टाई ने की इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत

जयपुर। राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर प्रेरित करने के लिए एक वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे पर टाई राजस्थान ने 'इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स' की शुरुआत की है। टाई द्वारा हाल ही नवोदित स्टार्टअप के लिए एक ग्रांट कार्यक्रम की घोषणा की गई। सितंबर माह में टाई अपने प्रमुख कार्यक्रम टाई स्मैशअप के जरिए राज्य भर से चयनित स्टार्टअप को एक साथ 22 से अधिक स्टार्टअप इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस आइडियाज को प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करेगा। इसको लेकर राज्य के चुनिंदा इमर्जिंग एंट्रेप्रेन्योर्स टिंकरली के शरद बंसल, फैब्रिकलोर के विजय शर्मा और फलीका के टीकम जैन के साथ पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें इन संस्थापकों ने स्टार्टअप स्थापित करने, फंड जुटाने, कठिनाईओं और सफलताओं की अपनी यात्राओं को साझा किया। टाई राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. रवि मोदानी ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर से फंडिंग जुटाने के साथ-साथ अपने स्टार्टअप को आईडिया से ग्रोथ स्टेज तक स्केल किया है।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

राजस्थान में, रेडीमेड गारमेंट्स की निर्यात वृद्धि 2018-19 में सबसे ज्यादा 2,078 करोड़ रुपए रही थी और 2021-22 में यह बढ़कर 2,561 करोड़ हो गई

छूट योजना में असंतुलन के कारण श्रम प्रधान उद्योग कर रहा है घाटे का सामना

जयपुर /लोकमत। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (RoSCTL) के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है।

RoSCTL को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं। विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (GEAR) ने कहा, कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है।

विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, तश्क्रूने कहा ऋभस्ष्ट्ठ्रु योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। स्क्रिप पर इतने ज्यादा डिस्काउंट से आयातकों को तो फायदा हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, 16 अरब डॉलर के कुल परिधान निर्यात में करीब 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होती है, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए बनती है। व्यापक स्तर पर, इस पर 20 से 25 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाता है, इससे परिधान क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मार्जिन पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए का सीधा असर पड़ता है।

इस योजना का उद्देश्य भारत के कपड़ा क्षेत्र को अन्य कम लागत वाले देशों जैसे बांग्लादेश और वियतनाम (कम श्रम और विनिर्माण लागत के कारण) के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना था। मांग सरकार की मंशा के अनुरूप रही है, जो हमेशा निर्यातकों को प्रतिपूर्ति करने की थी, लेकिन स्क्रिप के डिस्काउंट के कारण, इस पूरी योजना का उद्देश्य और लक्ष्य विफल हो गया है। अपने मौजूदा स्वरूप में, स्क्रिप पर डिस्काउंट से आयातकों को लाभ हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित फायदा उठा रहे हैं।

यह दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने के बजाय इस पूरी योजना के उद्देश्य और लक्ष्यों पर ही पानी फेर दे रहा है। अगर सरकार तत्काल ऋभस्ष्ट्ठ्रु की संरचना में संशोधन नहीं करती है, तो चिंता है कि लागत अक्षमताओं के कारण उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो सकता है। सरकार से उचित मदद न मिलने के कारण एक बार फिर परिधान मांग को अन्य कम लागत वाले देशों में स्थानांतरित कर देगी।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

छूट योजना में असंतुलन के कारण श्रम प्रधान उद्योग कर रहा है घाटे का सामना

- राजस्थान में, रेडीमेड गारमेंट्स की निर्यात वृद्धि 2018-19 में सबसे ज्यादा 2,078 करोड़ रुपए रही थी और 2021-22 में यह बढ़कर 2,561 करोड़ हो गई

जयपुर गुलाबी टाइम्स

जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीनें प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। RoSCTL को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को

बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं। श्री विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने कहा, कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। श्री विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, GEMA ने कहा RoSCTL योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। स्क्रिप पर इतने ज्यादा डिस्काउंट से आयातकों को तो फायदा हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, 16 अरब डॉलर के कुल परिधान निर्यात में करीब 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होती है, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए बनती है। व्यापक स्तर पर, इस पर 20 से 25 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाता है, इससे परिधान क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मार्जिन पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए का सीधा असर पड़ता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के कपड़ा क्षेत्र को अन्य कम लागत वाले देशों जैसे बांग्लादेश और वियतनाम (कम श्रम और विनिर्माण लागत के कारण) के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना था। मांग सरकार की मंशा के अनुरूप रही है, जो हमेशा निर्यातकों को प्रतिपूर्ति करने की थी, लेकिन स्क्रिप के डिस्काउंट के कारण, इस पूरी योजना का उद्देश्य और लक्ष्य विफल हो गया है। अपने मौजूदा स्वरूप में, स्क्रिप पर डिस्काउंट से आयातकों को लाभ हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित फायदा उठा रहे हैं। यह दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने के बजाय इस पूरी योजना के उद्देश्य और लक्ष्यों पर ही पानी फेर दे रहा है।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

जयपुर (कासं)। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीनें प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (ऋफ्स्ड्ढ्ळ) के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। श्री विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने कहा, कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, लधकृ ने कहा "RoSCTL योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

राजस्थान में, रेडीमेड गारमेंट्स की निर्यात वृद्धि 2018-19 में सबसे ज्यादा 2,078 करोड़ रुपए रही थी और 2021-22 में यह बढ़कर 2,561 करोड़ हो गई।

छूट योजना में असंतुलन के कारण श्रम प्रधान उद्योग कर रहा है घाटे का सामना।

जयपुर ■ संवाद सूत्र

राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (RoSCTL) के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है।

RoSCTL को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए 'मेक इन इंडिया' की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं।

श्री विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (GEAR) ने कहा, "कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है।"

श्री विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, GEMA ने कहा "RoSCTL योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है।

छूट योजना में असंतुलन — **वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित**

श्रम प्रधान उद्योग कर रहा घाटे का सामना

जयपुर (सीमा सन्देशसं)। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीनें प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है।

RoSCTL को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए 'मेक इन इंडिया' की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं। विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने कहा, कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष ने कहा RoSCTL योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है।

यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। स्क्रिप पर इतने ज्यादा डिस्काउंट से आयातकों को तो फायदा हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित, फलस्वरूप हो रहा घाटे का सामना

संजीवनी टुडे

जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने कहा, कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, क्क्ख्इ ने कहा टध्द्दए्ड्ख योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। स्क्रिप पर इतने ज्यादा डिस्काउंट से आयातकों को तो फायदा हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान व वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

वीर अर्जुन संवाददाता

जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है।

उद्योग के अनुमान के मुताबिक वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (RoSCTL) के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणाम स्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात

प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। (RoSCTL) को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं। श्री विमल शाह अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफराजस्थान (GEAR) ने कहा कि कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। श्री विजय जिंदल सदस्य एक्सपोर्ट प्रमोशन एईपीसी और अध्यक्ष (GEAR) ने कहा (RoSCTL) योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, 16 अरब डॉलर के कुल परिधान निर्यात में करीब 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होती है, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए बनती है। व्यापक स्तर पर इस पर 20 से 25 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाता है इससे परिधान क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मार्जिन पर लगभग 1500 करोड़ रुपए का सीधा असर पड़ता है।

वस्त्रण निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्रण उद्योग की प्रतिस्पनर्धा हो रही प्रभावित

जयपुर,(उदय टुडे)। राजस्थान वस्त् और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्यम का वस्त्रा निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीनें प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्रर से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, परिधाननिर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (RoSCTL) के कारण अपनेमार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणाम स्व रूप, राजस्थान के परिधान निर्यात कों को भी देशभर के अन्यत निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। RoSCTL को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इस का मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यात कों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इस के बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए मेकइन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं। श्री विमल शाह, अध्य क्ष, गारमेंट एक्स पोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थाजन (GEAR) ने कहा, कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्यं स्क्रिप्सम के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंशकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क् का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्पप के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्य,म से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वभरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्तन नकद हस्तां तरण हो रहा है।